श्री लाल कृष्ण आडवाणी: लोकतंत्र में इस प्रकार के डिज़ास्टर्स हैं तो उसकी व्यवस्था जनता करती है।

श्री सभापति: राजकुमार जी, अब छोड़िए आप, हो गया।

डा॰ अलादी पी॰ राजकुमार: सर, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे सैकिंड सप्लीमेंट्री पूछने दीजिए।

श्री सभापति: अच्छा ठीक है, पूछ लीजिए।

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: My second supplementary is very important, Sir. Has the Twelfth Finance Commission suggested involving the local bodies, voluntary organisations and NGOs to tackle the natural calamities wherever it occurs? I would like to know this from the hon. Minister.

श्री स्वामी चिन्मयानन्द: सभापति जी, जो अथारिटी बनाई गई है, उसमें बहुत सारी चीजें शामिल की गई हैं। उसमें यह कहा गया है कि वहां के चीफ सैक्रेटरी के नेतृत्व में अथवा चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में वे मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाएं या सैक्रेटेरिएट की कमेटी बनाएं और संबंधित विभागों के, जो साइक्लोन से प्रभावित विभाग होते हैं, उन सभी के सैक्रेटरी उसमें शामिल होंगे और इस तरह से वह कमेटी निरंतर सम्पर्क में रहेगी और स्थिति की मॉनिटरिंग करेगी।

*225. [*The questioner (Shri Bachani Lekhraj) was absent. For answer vide pages 39—44.*]

Financial help to J and K for handicrafts exports

*226. MISS MABEL REBELLO:
SHRI B.J. PANDA:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Jammu and Kashmir propose to boost handicrafts exports;

(b) whether Government have extended financial help to the State for infrastructural development in the sector;

(c) if so, the details thereof;

(d) whether Government have any similar proposal under consideration to help other backward States such as Orissa, Bihar and Madhya Pradesh, etc.; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI SYED SHAHNAWAZ HUSSAIN): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) Yes, Sir. Hon'ble Prime Minister has announced a special package for Jammu and Kashmir, to extend financial help to the State which includes infrastructure development as under:—

1. Setting up of Design Development-cum-Common Facility Centre-cum-Satellite Centre of Indian Institute of Carpet Technology (IICT) at Srinagar with a budget provision of Rs. 5.45 crores.
2. Provision of 32 stalls in India Exposition Mart at Greater Noida with a provision of Rs. 1.04 crores.
3. Setting up of Common Facility Centre at District level with a provision of Rs. 6.00 crores.
4. Setting up of Craft Development Institute at Srinagar at a cost of Rs. 9.63 crores.
5. Setting up of Urban Haat at Srinagar.

(d) and (e) The Government have not prepared similar package for any other State of the country. As the set of circumstances prevailing in the State of Jammu and Kashmir is special, the Special Package of Assistance has been announced for that State. However, the Package draws largely upon the existing Tenth Plan Schemes of the Ministry of Textiles benefits of which are available to all States of the country.

MISS MABEL REBELLO: Sir, I am happy that in the reply, it has been stated that the Prime Minister has announced special package to develop infrastructure to boost handicraft exports in Jammu and Kashmir. But, the same reply states that this package is drawn on the existing Tenth Plan scheme of the Ministry of Textiles which is available to all the States in the country. I would like to know, in this context, what is the financial assistance that is extended to Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Orissa, Bihar and Jharkhand for the last three years, because these are

very poor States and a number of people are artisans and are eking out their livelihood from handicraft sector. And, I would like to know whether the benefits, which have been given to the States, have reached the artisans, whether these artisans have come Above the Poverty Line, or, this money is being used only by bureaucrats and others to have good time for themselves.

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: सभापति जी, प्रधान मंत्री जी ने जम्मू-कश्मीर के लिए जो 6165 करोड़ रुपये का पैकेज अनाउंस किया था उसमें से 70 करोड़ रुपया टैक्सटाइल मिनिस्ट्री से रिलेटिड था। जम्मू-कश्मीर की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यह विशेष योजना बनाई गई थी। लेकिन हमने अपने जवाब में कहा है कि जो योजना हमारी मिनिस्ट्री के अन्तर्गत चल रही है उसी में इस योजना को भी शामिल किया गया है। हमारी मिनिस्ट्री में बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ उन स्टेट्स को एनजीओज़ के माध्यम से और सरकार के माध्यम से मिलता रहता है। उन्होंने जो प्रश्न उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश के बारे में पूछा है ....(व्यवधान)....

कुमारी मैबल रिबैलो: छत्तीसगढ़ और झारखंड के बारे में भी पूछा है। ....(व्यवधान)....

श्री सभापति: आप डिस्ट्रिक्ट भी बता दीजिए। ....(व्यवधान)....

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: सभापति जी, उसका तो पूरा विवरण ....(व्यवधान)....

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: सभापति जी, मैं उसकी पूरी लिस्ट उन तक पहुंचा दूंगा क्योंकि प्रश्न में उन्होंने तीन स्टेट का जिक्र किया था इसलिए मैं उनकी जानकारी यहां पर लेकर आया हूं और बाकी की जानकारी, उन्होंने जो डिटेल में मांगी है उसकी डिटेल मैं उनके पास भिजवा दूंगा।

श्री सभापति: जल्दी से भिजवा दीजिएगा।

MISS MABEL REBELLO: Sir, the handicraft sector provides direct employment to about 60 lakh people, mostly in the rural areas. And, it produces something like Rs. 17,000 crore worth of handicrafts, of which about Rs. 10,000 crores are for exports. I would like to know from the hon. Minister what is the mechanism that he is espousing to help the artisans to procure raw material at reasonable prices and sell their product in such a way that the money can directly reach them and not through traders and middlemen. Further, what steps does the Minister propose to take for improving the designs as per the market demand and constantly upgrading their skills so that their products are sold in the market, and

they can get good price? I would like to know what is the mechanism that he is going to adopt.

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आप यह बता दीजिए कि यह क्वेश्चन के स्कोप में आते हैं जो प्रश्न आपने पूछे हैं? आप बता दीजिए क्या ये प्रश्न आते हैं?

कुमारी मैबल रिबैलो: हां, इसमें आते है सर।

श्री सभापति: क्वेश्चन के स्कोप में आते हैं?

कुमारी मैबल रिबैलो: आप देख लीजिए।

श्री सभापति: श्री प्रेम गुप्ता जी। ...(**व्यवधान**)... गुप्ता जी आप बोलिए ...(**व्यवधान**)...

MISS MABEL REBELLO: Sir, does Government have any similar proposal?

श्री सभापति: आप छोड़िये। आप छोड़िये। मैंने आपसे पूछकर गलती की। ...(**व्यवधान**)...

MISS MABEL REBELLO: Sir, this comes within the purview of the question.

श्री सभापति: एक मिनट। श्री बी॰ जे॰ पंडा।

SHRI B.J. PANDA: Sir, these steps taken by the Government, which the hon. Minister has mentioned in his answer, are very laudable and Jammu and Kashmir certainly deserves special attention. But, Sir, infrastructure development is only one side of the coin. The other side of the coin is the marketing support that is required for exports. And, it is very obvious that this is lacking. When you look at the prices that the artisans get, whether it is for carpets in Kashmir or *ikat* textiles in Orissa, the prices that the artisans get, are very, very low compared to the prices at which we get these products in the markets in Delhi or abroad. My question to the hon. Minister is: what specific steps are being taken to provide marketing infrastructure, not just the developmental infrastructure?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: सभापति जी, हैंडीक्राफ्ट और आर्टिजन से जो हमारे लोग जुड़े हुए हैं और खासकर के बुनकर। उसके लिए हमारी सरकार बहुत चिंतित रही है जो कदम हमारी सरकार ने पिछले एक साल के अंदर उठाये हैं उनकी तुलना नहीं की जा सकती। इनका जो सवाल है एक तो वीवर्स और आर्टिजन के लिए तो हम लोग उनको क्रेडिट कार्ड देने जा रहे हैं ताकि उनको

मार्केटिंग के लिए वह पूंजी भी मिल सके जो आदरणीय प्रधान मंत्री जी के हाथों से 19 तारीख को हम वितरित करने जा रहे हैं। जहां तक इन्होंने सपोर्ट की बात कही है जो मार्केटिंग है उसके लिए हम लोग मार्केट और सपोर्ट सर्विस के लिए हमारी मिनिस्ट्री अलग से काम करती है, डिजाइन और टेक्नीकल अपग्रेडेशन के लिए हम उनकी मदद करते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए भी हम मदद करते हैं। ट्रेनिंग और रिसर्च डवलपमेंट के लिए भी हम उनकी मदद करते रहते हैं और इस तरह के बाजार लगाकर हम उनको, शिल्पियों को वहां पर पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं।

श्री प्रेम गुप्ता: सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्पैशल पैकेज जम्मू-कश्मीर को दिया, यह बड़ी खुशी की बात है। इससे हैंडीक्राफ्ट्स के ऐक्सपोर्ट में बहुत फायदा होता है और लोगों को इम्प्लॉयमेंट भी मिलता है लेकिन मान्यवर, जब बिहार और झारखंड का विभाजन हुआ था, उस वक्त बिहार के लिए भी पैकेज की अनाउंसमेंट की गयी थी कि हम 42000 करोड़ रुपए का पैकेज बिहार को देंगे। माननीय सैयद शाहनवाज हुसैन जी की कॉन्स्टीट्यूऐंसी में भी प्रधानमंत्री जी ने जाकर अनाउंस किया था कि बिहार को एक पैकेज देंगे। प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं और आप देश के कपड़ा मंत्री हैं। न आपने कोई पैकेज दिया और न ही प्रधानमंत्री जी ने कोई पैकेज दिया। क्या बिहार में आप कोई पैकेज नहीं देना चाहते, इस संबंध में बताइए।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: सभापति जी, यह सवाल कश्मीर के संबंध में है और कश्मीर की तुलना...

श्री सभापति: उनका प्रश्न यह है कि क्या आपने कोई ऐसी घोषणा की थी और अगर की तो क्या उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: महोदय, इन्होंने प्रधानमंत्री जी की घोषणा की बात की है। उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी होने के नाते वे सब घोषणाएं हमारे सर आंखों पर हैं। हम उस काम को कर रहे हैं लेकिन बिहार की...

श्री प्रेम गुप्ता: बिहार और झारखंड का विभाजन हुए डेढ़ साल से ज्यादा हो गया है लेकिन आज तक कुछ नहीं किया गया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: सभापति महोदय, जब मैं जवाब दे दूंगा तो वे इस बात को समझ जाएंगे। महोदय, बिहार पर हमारा खास ध्यान है – खासकर टेक्सटाइल सैक्टर में। ...(**व्यवधान**)..

श्री राजू परमार: कोई ध्यान नहीं दिया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री कपिल सिब्बल: पहली बार मंत्री जी ने सच बात बताई है। ..(**व्यवधान**)..

श्री अनिल कुमार: कोई ध्यान नहीं दिया। ...(**व्यवधान**)...

डा॰ कुमकुम राय: बिहार को कोई पैकेज नहीं मिला। ...(**व्यवधान**)...

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: सभापति जी, मैं स्वयं ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रेम गुप्ता: मंत्री महोदय देश के मंत्री हैं, बिहार से बिलांग करते हैं इसलिए उनको बिहार के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: वे कह रहे हैं कि आपकी तरफ इनका खास ध्यान है।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: प्रेम गुप्ता जी का प्रेम जब बाहर से जाकर बिहार के लिए इतना उमड़ सकता है तो...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: अब मैं प्रेम की बात यहां नहीं करने दूंगा। काम की बात करिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: मैं तो खुद बिहार का हूं तो मेरा प्रेम इनके प्रेम से कम कैसे हो सकता है?

Atrocities on dalits in Tamil Nadu

*227. SHRI K. CHANDRAN PILLAI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the increasing incidents of atrocities on dalits in the Southern districts of Tamil Nadu, particularly Madurai; and

(b) if so, the number of such cases reported during the last three years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI I.D. SWAMI): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The Government of Tamil Nadu have reported that there is no increase in the incidents of atrocities on dalits in the Southern districts of Tamil Nadu, particularly in Madurai district and the number of